उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): हां कल चलेगी।

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): जम्मू-कश्मीर की चर्चा कल भी जारी रहेगी। यह आज समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए ज्यादा अच्छा है कि साढ़े चार बजे जो लिस्टिड बिजिनस है, दो स्टेटमैंट्स हैं, क्लेरीफिकेशंस हैं, उनको समाप्त कर लिया जाए। सिर्फ तीन मिनट में सलीम साहब को क्यों खत्म करने के लिए कह रहे हैं?

श्री मोहम्मद सलीम: आपका मशवरा सर आंखों पर।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): महोम्मद सलीम साहब का तीन मिनट का समय कल तक के लिए रहा।

STATEMENT BY MINISTER

Incident of massacre of several people in Bhojpur District of Bihar on July 11, 1996

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): Madam, I am making a statement on the henious crime which has resulted in the massacre of several people on the 11th of July, 1996 in the Bhojpur District of Bihar.

Madam, the Hon'ble Members are aware that 19 persons were killed in village Bathani Tola, Barki Kharan under Sahar Police Station of Bhojpur district of Bihar on 11th July 1996. The facts of the incident as ascertained from the Government of Bihar are as follows. Around 60 armed activists of the Ranbir Kisan Mahasangh (Ranbir Sena) raided the village of Bathani Tola Barki Kharan on the afternoon of July 11, 1996. Eighteen persons were shot dead by them. Six persons were injured, of whom one also died subsequently. 12 houses were set ablaze destroying wheat, rice, clothes, etc. kept in these houses. The provocation for the attack seems to have been to settle scores with one Naimuddin Ahmad who was suspected of having killed two supporters of Ranbir Sena.

The Government of Bihar have also reported that 30 persons have been named in the report filed in the Sahar Police Station, along with others unknown. As on date, 22 persons had been arrested. Some firearms and ammunition have been recovered. One Sub Inspector and eight Other Ranks have been suspended for dereliction of duty. The Director-General of Police, Bihar and other senior police officials rushed to the site. The District Magistrate and Superintendent of Police have been camping there since the incident.

The dependents of those killed and the surviving victims have been provided immediate relief of Rs. 10,000/- each in cash. The families of the deceased have also been provided with 30 kgs. of rice and other essential commodities. The Chief Minister of Bihar visited the area on July 13, 1996 and announced relief @ Rupees one lakh to the next of kith and kin of the family of those killed. The Chief Minister also announced a relief of Rs. 2 lakhs to the family of Naimuddin Ahmad apart from the offer of a job in cases where the bread-winner has been killed. The Union Home Secretary has further ascertained that combing operations have been launched by Bihar Military Police and State Police in the area of four Police Stations, namely, Sahar, Sandesh, Piro and Udvant Nagar which are supposed to be strongholds of Ranbir Sena. People have been asked to surrender their arms and efforts are being made to disarm the Ranbir Sena activists.

While there is little doubt that adequate follow up action including rehabilitation of victims will be taken up by the State Government, much more is required to be done by the State. I would firstly not only need to enquire into the alleged inaction on the part of the policemen posted at the site of the incident but also go deeper to check out on the mind set of the law and order enforcement machinery. Then there is the question of empowerment of the weaker sections which always have to bear the brunt of the 'mighty'. A more effective strategy to implement various schemes relating to upliftment of these sections is obviously called for. The Central Government proposes to interact with the Bihar and

other State Governments to ensure ways and means to retain and enhance the efficacy of the administrative apparatus in the country. The presence of an effective and responsive administration only can prevent incidents such as the one in Bhojpur.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Now Members have to seek clarifications on the Statement.

श्री एस०एस० अहलुवालिया (बिहार): उपसभाल ध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री जी द्वारा वक्तव्य में बताया गया कि भोजपुर जिले में सहार थानान्तर्गत ग्राम-बथानी टोला, बड़की खारा में 19 व्यक्ति मारे गये। 11 जुलाई की यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना के पीछे रणबीर सेना का हाथ बताया जाता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्योंकि उनके इस वक्तव्य से यह जाहिर नहीं होता, पर अखबारों और टेलीविजन पर बताया गया है कि ये घटना निजी बदले की भावना को लेकर हुई है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले इस इलाके के लोगों ने रणबीर सेना के कुछ लोगों को मारा था जिसके बदले की भावना का तनाव वहां चल रहा था और गांव के लोगों के बार-बार अनुरोध करने पर कि हमारी और हमारे गांव की सुरक्षा व्यवस्था की जाये, पुलिस तैनात की जाये, उसके बाद भी राज्य सरकार ने कार्रवाई नहीं की। हमारे मुख्य मंत्री दिल्ली में मंत्री सभा के गठन करने के लिए व्यस्त थे और इस चीज पर ध्यान नहीं दे सके और यही कारण है कि वहां यह कोताही बरती गई तथा इस घटना का सामना करने के लिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी। मैं जानना चाहूंगा कि जब इस गांव की कम्पलेंट मिली थी तो उस पर क्यों कोताही बरती गई?

दूसरे महोदया, इस गांव में जो अस्त्र-शस्त्र सीज किये गये हैं, जो गोला-बारूद बरामद किया गया है, उसका ब्यौरा इस वक्तव्य में नहीं दिया गया है। जहां तक हमें अखबारों से कार्यकर्ताओं के माध्यम से खबरें मिली हैं कि वहां ऐके-47 और ऐके-56 का प्रयोग किया गया है। यह बात वहां के लोगों की लगी गोलियों से प्रमाणित होती है परन्तु टेलीविजन पर जो वस्तुओं की बरामदगी दिखाई गई है, उसमें कंट्री मेड बंदूकें दिखाई गई हैं और उसमें ऐसा दिखाया गया है कि ऐके-47 और ऐके-56 की गोलियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, अभी इन्होंने बतलाया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से दस हजार रुपये की तत्काल राहत दी गई और मुख्य मंत्री ने एक लाख रुपया और अगर उनके परिवार में कोई सदस्य नौकरी के योग्य है तो उस को नौकरी देने का वचन दिया गया है, परन्तु अभी तक यह निर्देश जिला कार्यालय तक नहीं पहुंचे हैं। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। महोदया, नईमुद्दीन अहमद को दो लाख रुपया अलग से दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? जितने और 19 आदमी मारे गये या उनके परिवार के सदस्य मारे गये, उनको एक-एक लाख रुपया और नईमुद्दीन अहमद को दो लाख रुपये देने के पीछे कारण क्या है? क्या उसकी जान-माल की कीमत और मरने वालों की जान-माल से ज्यादा थी? यह आंकड़ा कैसे आंका गया है?

महोदया, आरा के अस्पताल में जिन मरीजों को भर्ती किया गया है, उनका ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। पूरे गांव के लोग वहां पर गोलियों से आहत हुये, बम से आहत हुये या आग से आहत हुये अस्पताल में भर्ती हुये हैं, उनमें से कितने लोगों की हालत गम्भीर है, कितने लोगों की हालत सोचनीय है और कितने ठीक हो जायेंगे? इसका ब्यौरा भी नहीं दिया गया है। इसमें कई लोग विकलांग हो गये हैं, उनके हाथ-पैर काट देने पड़े है, छोटे-छोटे बच्चों को दिखाया जा रहा है। उस इलाके में इतना वहशीपन क्यों जागा है? और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या उपाय किए गये है? क्या इसमें एक केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री का हाथ है? रणबीर सेना को बैन करने के लिए वहां के कलेक्टर और पुलिस को बुलाकर कहा गया कि इनको खुली छूट दी जाये। उसके पीछे इस इलाके के केन्द्रीय राज्य मंत्री इसमें कितने जिम्मेवार हैं अगर जिम्मेवार हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होने जा रही है?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): डा० जगन्नाथ मिश्र।

डा० जगन्नाथ मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से, जितनी बड़ी दुर्घटना हुई है, उसकी गहराई पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि कोई ऐसी घटना हुई और एकाएक अकस्मात हत्या कर दी गई हो। स्थानीय कुछ विफलताएं हों और राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई हो। इसी वजह से यह नरसंहार हो गया है, यह आभास मिलता है इनके वक्तव्यों से। मै मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बिहार के उत्तर और मध्य भाग में लगातार ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, पिछले 5-6 वर्षों से। उग्रवादी गतिविधियां लगतार बढ़ती गई हैं। सरकार की

ओर से कोई प्रभावकारी कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। केन्द्र सरकार की तरफ से जो समय-समय पर हिदायतें दी गई हैं, उन हिदायतों पर भी अमल नहीं हुआ जिसकी वजह से यह समस्या बढ़ती गई। एक साल के भीतर ही भोजपुर जिले में लगभग 200 लोगों की हत्याएं हुई हैं, दोनो पक्षों की। अगर बिहार के उस भाग को देखा जाये तो एक साल के भीतर एक हजार से अधिक लोग मारे गये हैं। पंजाब और कश्मीर से भी अधिक व्यापक स्वरूप है उग्रवादी गतिविधियों के क्षेत्र में। न बिहार सरकार सही आंकलन कर पा रही है, न केन्द्र सरकार ध्यान दे रही है जिससे इस क्षेत्र में यह समस्या लगातार बढ़ती गई है।

इसलिए मंत्री महोदय से हम जानना चाहेंगे कि क्या बिहार के सुधार के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तत्काल केन्द्र सरकार की ओर से तैयार करेंगे? यह बात कही जाती है कि वहां पर जो निजी सेनाएं हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाने के बावजूद भी राज्य सरकार मुस्तैद नहीं है। क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर ऐसा दबाव दे सकेगी, क्या वह वास्तव में प्रतिबन्ध को प्रतिबन्ध बनाकर उस पर रोक लगा सकेगी?

दूसरी बात यह है कि बिहार में निजी सेनाएं चिपकी हुई हैं पिछले कुछ वर्षों के भीतर वह स्थानीय शासन इसलिए निष्क्रिय है, उदासीन है कि जान-माल की हिफाजत करने के लिए पुलिस की मिली भगत होती है स्थानीय दबावों के साथ इसलिए पुलिस से लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है। पुलिस के पास साधन भी नहीं होते हैं जितने साधन इन आतंकवादियों, उग्रवादियों के पास हैं उस अनुपात में पुलिस के पास साधन भी नहीं है कि अत्याधुनिक हथियार मुहैया कर सकें। क्या केन्द्र सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था होगी कि वहां के पुलिस शासन को पूरी शक्ति दी जाये और साधन दिये जायें तथा राज्य सरकार को मदद पहुंचाई जा सके?

साथ-साथ यह विवाद मजदूरों, गरीबों के बीच बांटी गई जमीन से संबंधित है कि वहां की जमीन सरकारी जमीन, हदबन्दी, बटाईदारी संबंधी विवाद, साहूकारों द्वारा अत्यधिक दर वसूल करने संबंधी विवाद ये सारे मामले हैं जिसकी वजह से यह घटनाएं लगातार बढ़ती गई हैं।

... ऐसे सारे मामले हैं जिनकी वजह से ये घटनायें लगातार बढ़ती गई हैं। मुठभेड़ें भी पुलिस के साथ हो रही हैं। अभी हाल ही में गया जिले में एक मुठभेड़ के तहत 9-10 उग्रवादी मारे भी गए हैं। अभी 11 तारीख के दो दिन पहले मुंगेर जिले के तारापुर जगह पर 9 लोग मारे गए हैं। बिहार के भिन्न भिन्न भागों में ये जो घटनायें लगातार हो रही हैं उनके कारणों की गहराई में राज्य सरकार जा नहीं रही है। क्या केन्द्रीय सरकार यहां से कोई विशेष दस्ता या विशेष बल या कोई विशेषज्ञों की समिति भेजने पर विचार करेगी जो इन हिंसात्मक घटनाओं की पृष्ठभूमि का सही आकलन कर सही रास्ता बता सके? हम ऐसा समझते हैं कि एक-दो घटनाओं को देखने से बिहार में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है। पिछले समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और वहां जनता दल की सरकार थी इसलिए उस वक्त आपस में तालमेल का अभाव भी था और केन्द्र सरकार की बात नहीं मानी जाती थी। लेकिन क्योंकि इस समय यहां जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है और गृह मंत्री उस दल से आते हैं जो गरीबों की समस्याओं के साथ अपनी हिस्सेदारी मानता आया है, इसलिए हमारी पूरी अपेक्षा है कि केन्द्र में जनता दल के नेतृत्व में जो सरकार है और उनके गृह मंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं, जिन्होंने भूमि विवादों में, भूमि सुधारों में दिलचस्पी ली है, क्या वह कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे ताकि पिछले 5-6 सालों में भूमि सुधार के मामलों में जो शिथिलता आ गई है, कमजोरी आ गई है, उसमें तेजी आए? सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्किसस्ट पार्टी सहित यू०एफ० सरकार दिल्ली में है और बिहार में भी जनता दल की सरकार है। तो क्या इन प्रगतिशील कार्यक्रमों में जो शिथिलता पिछले 5-6 सालों से हो रही है, जो कार्य 1990 से चल रहे थे, जो इन लोगों की सुरक्षा और संरक्षण से ताल्लुक रखते थे, उनको शिथिल कर दिया गया है तो क्या ऐसे कार्यक्रमों को चलाने में सरकार दिलचस्पी लेगी? जो भूमिसुधार कार्यक्रम शिथिल हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं और जो अब केवल पेपर पर किऐ जा रहे हैं और इसके कारण गरीबों के बेदखल किया जा रहा है और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। विशेषकर औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, भोजपुर, रोहताश, बेगूसराय और चम्पारण इन जिलों में इस तरह के विवाद उभर कर सामने आ रहे हैं और यहां उनकी व्यापकता दिखाई दे रही है। जैसा मैंने कहा एक साल के भीतर एक हजार लोगों को मारा गया है। ये कोई मामूली घटनायें नहीं हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर उजागर नहीं हो रही हैं। जिस प्रकार से कश्मीर और पंजाब की समस्यायें उजागर होती हैं, उस तरह से बिहार की समस्यायें उजागर नहीं हो रही हैं। फिर, आपके स्तर पर जो एक आम सहमति बननी चाहिए, जो एक चिंता होनी चाहिए वह चिंता बिहार के लिए नहीं हो पाई। भोजपुर में 18 लोगों का सामूहिक कत्ल केन्द्रीय सरकार को जागृत कर सका, केन्द्र सरकार को सजग कर सका। इसलिए केन्द्र सरकार को जागृत कर सका, केन्द्र सरकार को

सजग कर सका। इसलिए केन्द्र सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और इन घटनाओं की जांच करनी चाहिए।

अभी, हाल ही में वहा यह जो घटना हुई उसमें पिछड़ी जाति अल्पसंख्यकों के बच्चे और महिलायें उसमें अधिक है। महिलाओं और बच्चों का हाथ किसी विवाद में नहीं हो सकता। यह एक मानसिकता है, झगड़ा किसी मर्द से ही हो सकता है, लेकिन बच्चे और महिलाओं से ऐसा कोई विवाद नहीं हो सकता है। लेकिन उनका कत्ल वह पूरी मानवता पर एक कलंक है, हम पर कलंक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार इस घटना को एक सामान्य घटना समझकर और एक वक्तव्य देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेगी या इन घटनाओं की गहराई में जाते हुए बिहार में उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्था करने पर विचार करेगी और बिहार सरकार पर सख्ती करेगी और वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत करेगी? बिहार में कानून और व्यवस्था की जो स्थिति हो गई है उसमें हम ऐसा समझते हैं कि वहान पर 356 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। केवल विधि-व्यवस्था का सवाल नहीं है, केवल हत्याओं का सवाल नहीं है, वहां पर जो भ्रष्टचार का स्वरूप हो गया है हाल के दिनों में जो चारे घोटाले हुए है और जो अन्य विभागों के घोटाले हुए हैं, यह सब बताते हैं कि बिहार में शासन ... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): डा० मिश्र जी, एक मिनट .... (व्यवधान) ... एक मिनट। ... (व्यवधान)

डा० जगन्नाथ मिश्र: बिहार में शासन .... (व्यवधान) किसी प्रकार के ... (व्यवधान) .... देने में यह पूरी तरह से विफल है। ... (वयवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): यह कहने की जरूरत नहीं है... (व्यवधान) आप अपने को क्लैरीफिकेशन तक सीमित रखिए ... (व्यवधान)

डा० जगन्नाथ मिश्र: केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप करे और धारा 356 के तहत बिहार सरकार को बर्खास्त करके और प्रभावकारी कार्यवाही करके बिहार के लोगों और जनता की जान-माल ही रक्षा करे।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री वी० नारायणसामी। नारायणसामी जी, एक-एक मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए, भाषण देने की जरूरत नहीं है, केवल क्लैरीफिकेशन प्वायंट से पूछिए।

Kindly ask pointed questions. Don't go in for long lectures. Kindly put questions only.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Yes, Madam. Madam Vice-Chairman, thank you for giving me this opportunity. Madam, I do not want any kind of encomium or any kind of recognition from the CPI Members. You have given me directions, I will go by your directions. Madam, for the first time I find the hon. Home Minister, after the taking over of the new Government, is very free and frank. Madam, the Home Minister adds one word, he is too much free. Madam, he is saying that, I am not saying that. Madam, a massacre has taken place in Bihar and several innocent people were killed by Ranbir Sena. I do not know how many private senas are there in Bihar. *(Interruptions)* Madam, it was only a private enmity which led to the massacre. Madam, it teaches a lession to the State Government. Madam, I appreciate the statement of the hon. Home Minister. In the last sentence he said, "The presence of an effective and responsive administration only can prevent incident such as the one in Bhojpur." Madam, I would like to know from the hon. Minister whether the present Government of Bihar is irresponsive or ineffective. Let him say that. His last sentence is very damaging. He himself admits that there is a breakdown of law and order machinery in Bihar. What does he mean by using the words. "the presence of an effective and responsive administration only can prevent incidents as the one in Bhojpur"? Does the hon. Home Minister admit that there is a breakdown of law and order machinery in Bihar? Madam, I do not know whether the hon. Home Minister has got the information from the Bihar Government because he is giving out a fact that has been narrated by the Bihar Government. Has he got information about the latest weapons? He has said in his statement that some firearms and ammunitions have been recovered. What is the nature of the weapons? He has to

explain this. This statement should be made very clear. My colleague has mentioned that AK-47, AK-56 and the latest weapons have been seized. Is it a fact? The hon. Home Minister should tell me that. Madam, the Union Home Secretary has stated that there were ongoing operations in the areas where the massacre has taken place. What is the result? The result has not been mentioned. The combing operations have been launched by the Bihar military police and the State police in the area of four police stations namely Sahar, Sandesh, Puro and Udvant Nagar which are supposed to be strongholds of Ranbir Sena.

What is the result? Has anybody been arrested? How many persons have been taken into custody? The statement made by the hon. Home Minister should be very clear and candid. You have referred to 'combing operations'. What is the result of the 'combing operations'? This has to be explained by him.

The statement says that people have been asked to surrender their arms and that efforts are being made to disarm the Ranbir Sena activists. You say that you are trying to disarm the Ranbir Sena activists. What is your strategy? If you do not want to disclose, it is all right, but these people should be disarmed. When you say that people have been asked to surrender their arms, I would like to know as to how many have responded. These are the things, these are the questions, which the hon. Home Minister has to answer.

Madam, there is another damaging thing. In the fourth paragraph, the Home Minister has said: 'While there is little doubt that adequate follow-up action, including rehabilitation of the victims, will be taken by the State Government, much more is required to be done by the State'. Therefore, the Home Minister admits that the relief provided by the State Government is not sufficient, that much more has to be done, much more has to be done by the State Government for the purpose of protecting the lives of the people in that area.

Madam, under these circumstances, the statement made by the hon. Home Minister gives a clear evidence of the break-down of the law and order machinery in Bihar. The statement is very clear.

DR. JAGANNATH MISHRA: It is very clear.

SHRI V. NARAYANASAMY: That being the case, what are you going to do with the Bihar Government? The Home Minister has said that he is free, frank and forthright. Therefore, I appreciate the statement made by him. In the light of this statement, what are you going to do with the Bihar Government? As the Central Government, it is your duty to protect the lives of the people. When you have yourself admitted that there is no effective and responsive administration in Bihar, what action are you going to take? Kindly explain.

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं उस स्थान से होकर आया हूं। मुझे 13 तारीख को उस घटना-स्थल पर जाने का मौका मिला जहां लोगों को गोलियों से भूना गया और जो दूसरे परंपरागत हथियार हैं, उन से हत्या की गयी। एक ही आंगन के अंदर 18 लोगों की हत्या घटना-स्थल पर ही की गयी और एक-दो लोग अस्पताल में मरे।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप विवरण मत दीजिए, प्रश्न पूछिए।

श्री नगेन्द्र नाथ ओझा : महोदया, मैं ने वहां जाकर देखा है, इसलिए इतना बताना जरूरी था। महोदया, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां यह घटना घटी उस के चारों तरफ एक किलोमीटर से डेढ़ किलोमीटर के दायरे में चार पुलिस कैंप हैं। एक बड़की खड़ांव में, जहां यह घटना घटी उस का मुख्य गांव है। एक पतलपुरा में, एक मडिया स्कूल में, और एक घनरवा मिडिल स्कूल में। इन चार जगहों में पुलिस कैंप हैं। डेढ़ बजे से लेकर 3 बजे तक यह ताण्डव होता रहा, लेकिन क्या इन पुलिस कैंपों के पुलिस बल ने मूव किया? अगर नहीं तो क्यों? महोदया, यह प्रश्न इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह कोई आयसोलेटेड घटना नहीं है। इस के पहले भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। एक किलोमीटर

से कम के दायरे के अंदर पुलिस बल रहा है और घटना-स्थल पर नहीं पहुंचा है। क्या कारण है कि यह पुलिस बल नहीं पहुंचता है? क्या उन के पास पर्याप्त हथियार नहीं होते हैं? अपने बड़े हाकिमों से हुक्म लेने के लिए उन के पास दूसरे उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं या लापरवाही है? महोदया, मंत्री महोदय ने कहा कि जिम्मेदारी न निभाने के लिए कुछ पुलिस-कर्मियों पर कार्यवाही की बात हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस में उन पुलिस कैंप के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जिन पर यह कार्यवाही की जाएगी?

महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जब रणवीर सेना प्रतिबंधित है, तो फिर रणवीर सेना इस तरह की वारदातें क्यों करती आ रही है? इस रणवीर सेना पर आरोप आया है कि उस ने एक बारात पर हमला कर के 6 लोगों की हत्या की। फिर उस के बाद कई घटनाएं और कीं। तो फिर प्रतिबंधित होने के बावजूद एक आर्म्ड संगठन बिहार के अंदर किस ढंग से ऑपरेट कर रहा है? इस का क्या कारण है, इस पर भी मंत्री महोदय द्वारा प्रकाश डाला जाना चाहिए।

तीसरा मेरा प्रश्न है, अहलुवालिया साहब ने
5 P.M. जो यह प्रश्न किया कि नईमुद्दीन मियां के परिवार को दो लाख रुपए क्यों, तो मेरा प्रश्न है मंत्री महोदय से कि इन्हें दो लाख रुपए ही क्यों? मैं बताना चाहता हूं, नईमुद्दीन मियां के परिवार में पांच लोगों की हत्या हुई और उनकी एक बड़ी लड़की, जो 15 / 16 वर्ष की थी, के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या गोली मार कर कर दी गई। नौ-दस परिवार हैं, जिनमें दो परिवार में तीन-तीन की हत्या, किसी के परिवार में दो की हत्या, किसी परिवार में एक की हत्या और इसके परिवार में पांच की हत्या हुई है और जिसमें उसकी लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या हुई है। तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो पैसे, एक लाख या दस हजार रुपए दिए गए, किस आधार पर दिए गए? इसके किस आधार पर मंजूरी होती है? परिवार के आधार पर या एक एक मृतक के आधार पर? यह बिल्कुल स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो समाचार-पत्रों में बात आई कि प्रति मृतक, तो उस आधार पर पांच मृतक नईमुद्दीन के परिवार के होने से उन्हें कम से कम 10 लाख रुपया तो मिलना ही चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इसके साथ ही मैं एक और प्रश्न करना चाहता हूं। आप उनको पुनर्वासित करने की बात करते हैं। मेरा प्रश्न है कि आप कहां उनको पुनर्वासित कीजिएगा? मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, जो वहां मुझे लोगों ने बताया कि नईमुद्दीन मियां बड़की खडांव का रहने वाला था। 24 अप्रैल को वहां एक सुलतान मियां की हत्या के बाद वहां के 25 / 30 परिवार के लोग भागकर इस बथानी टोला पर आए और उन्होंने शरण ली थी एक चौधरी परिवार में और वहां सामूहिक नरसंहार की घटना हुई। यह पेशे से कोई दूसरा काम करने वाला नहीं है। यह मनिहारी का काम करने वाला है, जो सुहागिनों को चूड़ी पहनाता है। जो सुहागिनों को चूड़ी पहनाता है, आज उसके परिवार में सुहाग का सिन्दूर घुला है। उसके परिवार में इतनी हत्याएं हुई हैं। एक हजार से ज्यादा चूड़ियां टूटी हुई, बिखरी हुई मैंने वहां देखी हैं। क्या जिस गांव के 25 / 30 परिवार आए थे, बड़की खड्डांव जो सामंतों का गढ़ है वहां आप पुनर्वासित करने की व्यवस्था कीजिएगा या किसी अन्यत्र जगह, जहां वे सुरक्षित और अमन चैन से रह सकें वहां व्यवस्था कीजिएगा? कहां व्यवस्था कीजिएगा?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): अब आप समाप्त करें।

इसके अलावा और भी प्रश्न हैं, लेकिन महोदया की परमीशन नहीं है इसलिए मैं बैठता हूं। इतना भी अगर मंत्री महोदय उत्तर दें संतोषजनक, तो हम समझेंगे कि गरीबों के लिए और जो ऐसी बार-बार आहत और टीस होती है उसके लिए यहां से भी कुछ हो सकेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ यह देखकर कि ऐसे मौकों पर भी, ऐसे प्रश्नों पर भी, यहां हंसने और मुसकराने वाले मिल गए, क्षमा करेंगे। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मैं सदन की राय जानना चाहती हूं। यह 5 बजकर 3 मिनट हो रहे हैं और नागरिक उड्डयन मंत्री यहां बैठे हुए हैं। इनका भी आज वक्तव्य होने वाला है।

श्री एस० एस० अहलुवालिया: कल होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): तो अगर सदन की राय हो तो यह अपना वक्तव्य दे दें। दोनों वक्तव्यों के ऊपर जो क्लैरीफिकेशन पूछे जाएंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री एस० एस० अहलुवालिया: आज गृहमंत्री अपना जवाब दे दें, बस।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: It is a sensitive issue. The Home Minister's clarification should be made today.

SHRIMATI MARGARET ALVA: We will sit and wait.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): तो उड्डयन मंत्री जी कल अपना बयान दें?

श्री एस० एस० अहलुवालिया: जी, कल।

नागर विमानन मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहिम): मैडम, जैसा आपका आदेश होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आज तो समय नहीं रहेगा। ...(**व्यवधान**)... तो सदन की राय है कि आप लोग अभी बैठना चाहते हैं।

डा० जगन्नाथ मिश्र: सदन की राय है, होम मिनिस्टर का जवाब सुनना है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Home Minister's clarification...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठकर मत बोलिएगा, खड़े होकर बोलिएगा जो आपको बोलना है।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): I apologize, Madam. Since the issue is extremely sensitive and has been agitating the mind of the nation as a whole, and not only the people of Bihar, I suggest that the hon. Home Minister may kindly complete his clarifications today. We would like to know from the Government what steps the new Government is likely to take in order to prevent this type of genocide in any part of the country.

SHRI V. NARAYANASAMY:*

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: No, no. This is too much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Narayanasamy's remark will not be entitled to be in the proceedings.

श्री गया सिंह (बिहार): मैडम, बाकी बात तो श्री नगेन्द्र ओझा ने कर दी है, नगेन्द्र जी के साथ मैं भी वहां गया था, इसलिए जितनी चर्चा उन्होंने की है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं होम मिनिस्टर साहब को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र में जैसा कि डा० साहब ने कहा, पिछले 10 साल से ये घटनाएं हो रही हैं और इनके मुख्यमंत्रित्व-काल में ही रणबीर सेना की स्थापना हुई, यह मैं सूचित करना चाहता हूं। मिश्र जी जब मुख्य मंत्री थे, उस समय उस क्षेत्र की विधायक भी उन्हीं की पार्टी की थीं—ज्योतिष जी —और उस इलाके में जिस तरह की घटनाएं हुई, बेलौर गांव में, और रणबीर सेना की स्थापना इनके मुख्यमंत्रित्व-काल में हुई।...(**व्यवधान**)...

डा० जगन्नाथ मिश्र: इनको ज्ञात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है।

डा० जगन्नाथ मिश्र: यह मिथ्या है, इनको मालूम नहीं है कि वह 1983 का जमाना था और यह अभी लालू यादव की बनाई हुई है।...(**व्यवधान**)... यह सेना लालू यादव की बनाई हुई है। ...(**व्यवधान**)...

श्री गया सिंह: सुनिए, सुनिए।...(**व्यवधान**)... मैं उसमें नहीं जाना चाहता, सिर्फ याद दिलाया चूंकि होम मिनिस्टर साहब को ...(**व्यवधान**)...

श्री एस०एस० अहलुवालिया: गया सिंह जी, क्या जस्टिफाई करना चाहते हैं इसको? आरोप-प्रत्यारोप मत कीजिए, वर्तमान पर बात कीजिए।

श्री गया सिंह: मैं आ रहा हं उसी पर। ...(**व्यवधान**)... सुनिए, सुनिए। सुनने का धैर्य तो रखिए। ...(**व्यवधान**)...

डा० जगन्नाथ मिश्र: सारे कार्यक्रम आपने भुला दिए और लालू यादव जी को समर्पित करके सारे भूमि सुधार कानून खत्म कर दिए, यह उसी का नतीजा है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आप चेयर को एड्रेस करके बात करें, इनके साथ आपस में वार्तालाप नहीं करें।

श्री गया सिंह: मैडम, मैंने सिर्फ याद दिलाया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां चारों तरफ जो एक किलोमीटर पुलिस, जिसकी चर्चा इन्होंने की और वहां जाने के बाद यह पता चला कि जो फोर्स है केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार ने पहले से वहां के थाना और पुलिस के पास जो हथियार, राइफल्स हैं, काफी छीना भी गया, जिसकी चर्चा हुई और वहां उग्रवादी या रणवीर सेना या प्राइवेट सेना के पास जो हथियार हैं, ए०के०-47 या दूसरे, वे हमारी पुलिस के पास नहीं और हमारी पुलिस या स्टेट गवर्नमेंट को वह मुहैया नहीं कर पा रहे हैं। यह कारण है या नहीं, इसकी जांच करने की जरूरत है। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर की बात करके अगर लीपा-पोती करेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, उससे संबंधित जो भी चर्चा हो यहां, होम मिनिस्टर उसका जवाब दें। मैं समझता हूं कि इसका समाधान सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से

*Not recorded.

नहीं है क्योंकि पिछले 10 साल से ये जो घटनाएं हुई हैं, एक नहीं, जिसकी चर्चा आपने की है, कई घटनाएं हुई हैं, काउंटर होता है हर दो महीने बाद। अभी दो महीने पहले रणबीर सेना के ऊपर भी हमला हुआ और 9 लोग मारे गए उनके, राढी गांव है वहां, अभी दो महीने पहले। उसके दो महीने पहले दूसरे लोगों ने किया। तो यह जो घटनाएं हो रही हैं, हमारा उसमें सुझाव है कि अगर होम मिनिस्टर उसमें सहमत हों, पहला तो यह है कि माननीय होम मिनिस्टर को वहां जाना चाहिए और...

एक माननीय सदस्यः जा रहे हैं।

श्री गया सिंहः जा रहे हैं तो उसकी चर्चा हो। आप बताइए, अगर वहां जाना चाहते हैं तो जाएं, जाने के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के अलावा उस इलाके के जनप्रतिनिधियों—एम०एल०ए०, एम०पी० और विभिन्न पोलिटिकल पार्टियों के साथ इसकी चर्चा करके अगर परसुएशन की बात नहीं होगी तो सिर्फ लॉ एंड आर्डर की बात कहकर हमारे मिश्र जी चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। इसका समाधान नहीं होगा क्योंकि यह पहली घटना वहां नहीं है, 10 साल से घटनाएं हो रही हैं। 60 हजार एकड़ जमीन परती है दस साल से और वह जनता दल की सरकार के समय से सिर्फ नहीं है, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं कि बेलोर गांव से, जहां 4 हजार एकड़ जमीन कई साल से परती है, इनके जमाने से भी पहले से—दूबे जी थे, उनके जमाने से घटनाएं हो रही हैं। इसलिए यह सीरियस मामला है और लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है, उसको तो आप मेकअप कीजिए, जो दूर करना है लेकिन सोश्यिल सवाल है वहां, वहां पिछड़ापन भी है, सामंती लोग भी हैं, दूसरी तरफ के लोग भी हैं, उसका जो मिस-यूज़ कर रहे हैं पोलिटिकल ढंग से, उसको ठीक करने की जरूरत है। 40 किलोमीटर के अंदर की ये घटनाएं हैं और आर्म्स बहुत हैं। इन आर्म्स को डिसआर्म्स करने के लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए पोलिटिकल, सोश्यिल लेवल से परसुएशन करके शांति लाने की जरूरत है। इसलिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, दोनों को मिलकर तमाम पार्टियों के साथ बातचीत करके इस दिशा में प्रयास करना चाहिए जिससे यह कश्मीर की समस्या हल हो सके।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): आपका प्रश्न क्या है? आप तो सुझाव दे रहे हैं।

श्री गया सिंहः सुझाव दे रहा हूं, स्पष्टीकरण भी मांग रहा हूं। इसलिए मेरा सुझाव है कि गृह मंत्री वहां जाएं और वहां जाकर इन चीजों को देखें।

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated): Madam Vice-Chairman, one part of my question has already been asked. I had been to Gaya and other places, and I have seen them. It is basically a political social issue. This issue between land-owners and landless people is not confined to Bihar only but it has spread to other States also.

There is another aspect which is developing in this country. As we have the Ranvir Sena, there are other senas also coming up in other parts of the country. I would like to know first from the Minister what action the Government is going to take to see that no such sena first of all comes up because wherever a sena comes up, it is within the knowledge of the police whether the sena has started or not started.

Madam, if we take the case of Bihar, it is not only the people that are divided, but even the police force is also divided, not at the higher level but at the lower level. Wherever there are police camps. In the camps, every community has its own kitchen. This divison has come into the police forces. That is reflected in the law-and-order situation. This is spreading, as far as I know, from Bihar to other States also. Therefore, my second suggestion to the Minister will be to see that the police force is not divided on community basis. When it starts from the kitchen itself, cooking itself, when one community cooks, other communities do not share the food, when this kind of sentiments are developing in the police force, you can imagine, if this situation deteriorates, what kind of situation will develop. Therefore, my second question relates to this. What is the Government going to do to see that this is stopped in the police force and what means is the Government going to adopt to see that this is going to be stopped?

Thirdly, wherever there are land tensions between land-owners and landless or other social tensions, these tensions do not develop overnight. They take a period of time. We have the Government

machinery, we have the police machinery and we have other machineries also wherein information is collected. It is quite possible that sometimes it is at the district level or at a lower level. The situation gets into a form. They get into the tension which is developing. That is stopped. Sometimes it does not stop. If it goes beyond control. Unless there is an explosion, nothing is done. In such a situation, I would like to know from the Government, if those who are going to be victimised, know that they are going to be victimised and if they approach the Government that they should be armed for a particular period of time, whether the Government is going to think in terms of giving arms for self-protection.

Thank you, Madam.

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Hon. Vice-Chairman, thank you for this opportunity given to me to communicate my feelings to the House. Let me join the entire country in the nation-wide shock and indignation over the ghastly genocide that took place in Bhojpur, including pregnant women and innocent children. This is an incident of national shame. It is quite unfortunate that such national scars are not infrequent even in the penultimate year of the Despite that, amidst this environment of grief and national shock and in one of the rarest occasions after such cruel incidents, the hon. Home Minister has come out with a statement which was not perfunctorily done. It reflects a change in the climate of the governance. Now, my questions before the Home Minister are:

First, are the Government planning any ban and perpetual prohibition against all landlord outfits in Bihar, not only against the Ranvir Sena who has been perpetuating this kind of crimes for the last 49 years?

My second question have we any reason to believe that these landlord outfits are not enjoying the backing of any political element or even political forces?

My third question is, are the Government planning a national comprehensive action programme to prevent similar incidents, ghastly genocides, massacres and atrocities against agricultural labourers, the poorest sections of society, dalits, dalit women, minorities tribals and other disadvantaged and backward sections of the society?

My last question is, if article 356 is an answer to all these crimes which have been perpetrated in the last 49 years, whether the number of applications of article 356 in Bihar would not have exceeded the number of governments in Bihar in the last 49 years. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Thank you Mr. Mr. Bratin Sengupta. This was his maiden speech.

SHRI BRATIN SENGUPTA: Thank you for recognition.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRIMATI KAMLA SINHA) Honourable Member, Shri Raj Nath Singh.

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदया, निश्चित रूप से यह बिहार की घटना लोम हर्षक है, हृदय विदारक है। यह दुखद् भी है, दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक भी है और जैसा पूर्व वक्ताओं ने बतलाया और बिहार के कई संम्मानित सदस्यों ने बतलाया कि वहां पर लगातार कई वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं चल रही है और अभी डा॰ जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा कि एक वर्ष के अंदर ही वहां पर एक हजार से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है और यह क्रम अब भी चल रहा है। भोजपूर की जो घटना घटित हुई है वह प्रतिशोध के परिणामस्वरूप घटित हुई है। लेकिन मुझे दुख यह है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें निष्पक्षता और ईमानदारी का परिचय नहीं दिया है। मैं सीधा आरोप लगाना चाहता हूं। क्योंकि अंतिम पैरा में आपने लिखा है—"सरकार द्वारा बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। पहले तो घटना-स्थल पर तैनात पुलिस कर्मियों की न केवल कथित निष्क्रियता की जांच करने की जरूरत है अपितु कानून और व्यवस्था लागू करने वाले तंत्र की मनोस्थिति की छानबीन करने के लिए गहराई तक जाने की भी जरूरत है।"

आपने सरकार को बचाने की कोशिश की। पुलिस कर्मियों को, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहां के ब्यूरोक्रेट

को तो आपने जुम्मेदार ठहराया है। लेकिन इतनी सारी घटनाएं हो गई और आप इस सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महोदया, अयोध्या में एक विवादित ढांचा गिरने के कारण चार चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की जा सकती है तो उस बिहार में एक हजार लोगों की एक वर्ष में हत्याएं हों और अब भी वहां की सरकार बनी हुई है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां पर आपने चिंता व्यक्त की है कि सारे मामले की गहराई तक जाने की जरूरत है। तो क्या केन्द्र सरकार के द्वारा वहां पर ऐसी एजेंसी भेजना आपकी योजना में है अथवा नहीं? महोदया, मुझे लगता है कि अब बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहां जंगल राज कायम हो गया है। हमारी तो यह मांग है कि एक कमीशन बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए जो कि बिहार में खुद जाकर, एक महीने में, 15 दिन में यह काम पूरा नहीं होगा उसके लिए दो महीने, तीन महीने भी लग सकते हैं। तो ऐसा आयोग बने और जाकर वहां की सारी सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमंडेशंस भारत सरकार को निश्चित समयावधि में प्रस्तुत करें। यह मैं मांग करना चाहता हूं और साथ ही आपने एक चिंता व्यक्त की है कि कमज़ोर वर्गों को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है और सदैव शक्तिशाली लोगों के जुल्म कमज़ोर लोगों को सहने पड़ते हैं, यह आपने चिंता व्यक्त की है अपने वक्तव्य में तो मैं यह भी जानना चाहूंगा आपसे कि इन कमज़ोर लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या आपके पास कोई रणनीति है? कोई आपके पास योजना है? मैं अंतिम निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार से इस वक्तव्य को तैयार करने में निष्पक्षता और ईमानदारी का परिचय नहीं दिया गया है और इसी प्रकार का क्रम चलता रहा आगे तो इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहेंगी, इन पर कभी भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बिहार में अनवरत इसलिए घटती जा रही हैं क्योंकि यह सरकार की आदत हो गई है कि अपने हर फैसले को वोट के तराजू पर तोलने का काम करती है बल्कि सच बात तो यह है कि किसी भी सरकार को, हुकूमत करने वाली सरकार को, ईमानदारी से हुकूमत करने वाली सरकार को अपने फैसले को वोट के तराजू पर नहीं तोलना चाहिए बल्कि इंसाफ के तराजू पर तोलना चाहिए और न्याय के तराजू पर तोलना चाहिए। इसी निवेदन के साथ महोदया मैं समाप्त करता हूं।

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदया, गृह मंत्री जी के वक्तव्य के बाद यह बात निश्चित तौर पर साबित होती है कि बिहार के अंदर आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि रणबीर सेना जैसे कितने संगठन सक्रिय हैं बिहार में? प्रतिबंधित होते हुए भी ये संगठन काम कर रहे हैं। वहां की सरकार इन संगठनों को रोकने के लिए क्या प्रयत्न, क्या कार्यवाही कर रही है? 12 घर जला दिए गए, मैं यह जानना चाहूंगा कि ये 12 घर किसी एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों के थे या अलग-अलग सम्प्रदाय के लोगों के थे? और इन घटनाओं के पीछे एक पुलिस उप-निरीक्षक और आठ छोटी रैंकों के कर्मचारियों को निलम्बित किया गया। इससे यह लगता है कि बिहार के अंदर जो पुलिस प्रशासन है, उसको यह जानकारी है कि घटनाएं होंगी और उन घटनाओं के पीछे किन लोगों का हाथ है? पुलिस प्रशासन उसमें सक्रिय है। निष्क्रियता इसलिए है कि उस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन का भी हाथ है। आज गृह मंत्री जी ने प्रशासन को, वहां की व्यवस्था को दोषी मानते हुए बात कही है तो मैं यह गृह मंत्री जी से चाहूंगा कि आप कारगर और जवाबदेह प्रशासन के लिए क्या कदम उठाएंगे वहां पर या वहां की जो राज्य सरकार है, जो आए दिन ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदारी निभाती नहीं है, क्या रणवीर सेना जैसा संगठन लालू सेना का भी है जो इस प्रकार की घटनाओं में सम्मिलित रहता है? दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन से राजनीतिक दल का सपोर्ट है रणवीर सेना को, यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा मारे गए .....(**व्यवधान**).....

SHRI K.R. MALKANI (DELHI): What is happening here? Who has mentioned the name of BJP and on what basis?

(Interruptions).

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): माननीय सदस्य, अगर बैठकर कुछ बोले तो आप उसको नोटिस में न लें। मलकानी जी ...(**व्यवधान**)...

डॉ० जगन्नाथ मिश्र:*

उपसभाध्य: (श्रीमती कमला सिन्हा): कोई बात प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगी।

श्री एस० एस० अहलुवालिया:*

उपसभाध्यक्ष: (श्रीमती कमला सिन्हा): मेरी इजाजत के बिना यह सब जो बोल रहे हैं, यह प्रोसीडिंग्स में नहीं जाएगा। आप बैठ जाइए। जनार्दन यादव जी, आप भी बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

*Not recorded.

श्री मूलचन्द मीणा: मैंने किसी राजनैतिक दल का नाम नहीं लिया है। मैंने गृह मंत्री जी से जानना चाहा है कि रणबीर सेना को किस राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त है? जो आदमी चोर होता है, तो पहले ही उसे आग लगती है। ...(**व्यवधान**)... जब बात सामने आती है ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): मीणा जी, अनपार्लियामेंटरी शब्द इस्तेमाल न करें। बस अब आप समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी: बी० जे० पी० के कारण ...(**व्यवधान**)...

श्री मूलचन्द मीणा: दूसरे, मैं यह जानना चाहूंगा कि कमजोर वर्गों को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? कमजोर वर्गों को शक्तिशाली बनाने की बात तो सभी करते है। जब कभी घटना घटती है, सदन में बात उठती है, कमजोर वर्गों की सहायता के लिए काम करने की बात होती है। ...(**व्यवधान**)

श्री महेश्वर सिंह: आपके तो सिर में भी दर्द हो तो उसका कारण भी बी० जे० पी० है। ...(**व्यवधान**)

श्री जनार्दन यादव: इतनी हत्याएं हुई। यहां बातें होती हैं ...(**व्यवधान**)

श्री मूलचन्द मीणा: जब भी सदन के अंदर ऐसी घटनाओं पर चर्चा होती है तो एक ही बात सरकार की ओर से होती है कि गरीब लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए, ताकतवर लोगों से उनकी रक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। बिहार के अंदर विशेष तौर पर प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार के अंदर आए दिन घटनाए घटती है। रात को तो हम बिहार की सड़कों पर चल नहीं सकते, ऐसी स्थिति वहां पर है। ...(**व्यवधान**)... आप गरीब लोगों की रक्षा के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं जिससे ताकतवर संगठनों से, जो साम्प्रदायिक संगठन हैं उनसे, और जो उग्रवादी संगठन हैं उनसे, गरीब लोगों की रक्षा की जा सके। यह मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

श्री नरेश यादव: (उत्तर प्रेश) उपसभाध्यक्ष महोदया, निश्चित तौर पर भोजपुर के बड़कीखारा गांव में जो घटना घटी है, वह दुखद है। इस संबंध में जिस ईमानदारी और निष्पक्षता से माननीय गृह मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है, उसके लिए मैं गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी से हिन्दी में जिन्होंने अनुवाद किया, उनसे थोड़ी गलती हो गयी है। अगर चौथे पैरा को शुरू में पढ़ा जाए "जबकि इस बात में संदेह नहीं कि राज्य सरकार द्वारा पीड़ितों के पुनर्वास सहित पर्याप्त समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी .....।" इसमें निश्चित तौर पर "की जाएगी" के स्थान पर "की जा रही है" अनुवाद होना चाहिए था। की जाएगी नहीं। की जा रही है।

एक माननीय सदस्य: खबर है कि 'की जाएगी' तो कैसे कह दें कि की जा रही है।

श्री नरेश यादव: महोदया, जिस तत्परता से 11 तारीख की घटना घटने के बाद बिहार सरकार ने कदम उठाया है, बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए क्योंकि मौके पर भारत सरकार के एक राज्य मंत्री, बिहार सरकार के मुख्य मंत्री, वहां के जो महानिरीक्षक हैं, वह गए और उन्होंने सक्षम कार्यवाही की। वहां पर जो घोषणा उन्हें करनी चाहिए थी, उन्होंने की और उस पर अमल भी कर रहे हैं।

आज एक बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि पार्टी से ऊपर हट करके सभी माननीय सदस्य इस बात को गम्भीरता से लें। पक्ष-विपक्ष दोनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह घटना नई नहीं है, चाहे हमारे डाक्टर मिश्रा जी मुख्य मंत्री रहे हों। इसके पहले भी अनेक लोमहर्षक घटनाएं घटी हैं और इसके पीछे कारण सामन्तवादी व्यवस्था है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): क्वेश्चन पूछिए, सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री नरेश यादव: उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं सीधे प्रश्न कर रहा हूं। वहां पर अधिक लोग जमीन से वंचित हैं जिसके कारण भू-समस्या के चलते विवाद होता रहता है। कोई अपराध बिहार में नहीं है जैसे कि श्री मीणा जी और साथी कहते हैं कि बिहार में चलना दूभर है। ऐसा लगता है कि बिहार में रेलगाड़ी, हवाई जहाज और मोटर गाड़ी चलती ही नहीं है। बिहार में शांति है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में कोई समस्या है तो सिर्फ लड़ाई-झगड़े की सामंती व्यवस्था को लेकर है। उपसभाध्यक्ष महोदया, एक बात कह कर मैं समाप्त करना चाहूंगा कि देश में जितनी भी सेनाएं हैं जैसे रणबीर सेना है, ये जितनी सेनाएं वे जाति, धर्म और महर्षि के नाम पर हैं और ईमानदारी से अपने कलेजे के ऊपर हाथ रख कर के देखे कि जो राजनीतिक संगठन सेनाओं के नाम पर बनाये गये है वे जो जाति के बड़े पुरुष हो गये, वह चाहे ब्रह्मऋषि हो गये, चाहे वह बाल्मीकी हो गये, चाहे कोई भी शंकर जी हो जाये, कोई

हो जायें। तमाम लोग जो जाति के, धर्म के, देवताओं के नाम पर संगठन बनाए हुए हैं क्या गृह मंत्री जी उन पर प्रतिबन्ध लगाने जा रहे हैं? मैं भारत की सेना मान सकता हूं स्टेट की सेना मानी जा सकती है लेकिन सेनाएं धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर नहीं चलने वाली हैं। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि धर्म, जाति और देवताओं के नाम से बनने वाली सेनाओं पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जनार्दन यादव (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं जगन्नाथ जी और लालू जी के झगड़े में नहीं जाना चाहता हूं। बिहार में जो लालू जी हैं वहीं जगन्नाथ जी हैं और दोनों अपने-अपने समय में*

श्री नरेश यादव: यह सरासर गलत आरोप है। (...व्यवधान..,.)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): श्री जनार्दन यादव जी आप प्रश्न पूछिए (...व्यवधान...)

श्री जनार्दन यादव: दलित, पिछड़े मारे गये हैं, 21 मारे गये हैं और इसी मुख्य मंत्री के राज में गेजुआ में 42 भूमिहार एक ही जाति के मारे गये थे, यह आपको याद होगा। इसलिए मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार लालू जी की रहे, जनता दल की रहे, जगन्नाथ जी की रहे, कांग्रेस की रहे, गरीब लोग मारे गये हैं, मारे जा रहे हैं। अब गरीब नहीं मारे जाये, इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्री जी बिहार में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? यह सिर्फ भोजपुर जिले का ही सवाल नहीं है बल्कि बिहार के दस ऐसे जिले हैं जहां मास किलिंग प्रत्येक महीने में, प्रत्येक पखवाड़े में, प्रत्येक सप्ताह में हो रहा है। गया बाबू बोल रहे थे कि बिहार पुलिस के पास सोफिस्टीकेटिड आर्म नहीं हैं। सचमुच में बिहार में चाहे वह उग्रवादी हो, चाहे प्रादेशिक सेना हो या रणवीर सेना हो इनके पास सोफिस्टीकेटिड आर्म है, इसीलिए बिहार पुलिस इनका सामना नहीं कर सकती है।

साधारणतया जो गरीबों के गांवों में गरीबों को बचाने के लिए पुलिस फोर्स का शिविर लगा होता है, वहां जीप नहीं होती है अगर जीप होती भी है तो पैट्रोल नहीं होता है। ये जो 8 जिले हैं इनमें मुझे याद है है कि सैकड़ों पुलिस शिविर हैं जिस गांव में पुलिस शिविर लगा है वहां भी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हमारे बिहार के मुख्य मंत्री तथा बिहार-सरकार की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। उस इच्छा शक्ति को जगाने के लिए हम केन्द्र सरकार के गृह मंत्री से आग्रह करना चाहते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति कैसे आप जगायेंगे। गरीबों की सुरक्षा कैसे होगी? अगर वर्गों में बांटकर के मुआवजा दिया जायेगा अगर जाति के नाम पर क्रिमनल मारा जाता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जायेगा। क्या उस राज्य में गरीब, कमजोर अधिक दिन जी सकता है? वहां की सरकार में जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नजदीक रहते हैं, उनके सिर पर फूल-मालाएं चढ़ाई जाती हैं। इसलिए आपसे आग्रह है ... (व्यवधान ...) समस्या मैं बता रहा हूं। सवाल तो ... (व्यवधान ...)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): जनार्दन जी एक तो आपको उस तरफ देखकर बात नहीं करनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि आप प्रश्न पूछें, आपको व्याख्यान नहीं करना है। प्रश्न पूछिये सीधे-सीधे।

श्री जनार्दन यादव: मैं आपके माध्यम से भारत के गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि यह जो रणवीर सेना के नाम से संगठन चला था उसको प्रतिबंधित किया गया, लेकिन दल पर, संगठन पर प्रतिबंध किया गया है, उस संगठन का व्यक्ति सड़क पर हथियार लेकर घूम रहा है। वह पकड़ा नहीं गया है। वह कब तक पकड़ा जाएगा ... (व्यवधान ...)

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): इन रणवीर सेना का सरगना कौन है ... (व्यवधान ....)

श्री जनार्दन यादव: सरगना कौन है ... (व्यवधान ...) यहां तो आप भी समर्थन दे रहे हैं ... (व्यवधान ...)

श्री मोहम्मद सलीम: पकड़ते क्यों नहीं? ... (व्यवधान ...) पकड़ते क्यों नहीं ... (व्यवधान ...)

श्री जनार्दन यादव: मैं भा०ज०पा० का कार्यकर्ता होने के नाते यह कहता हूं कि नरसंहार पर भा०ज०पा० का विश्वास नहीं है और किसी भी प्राइवेट सेना का समर्थन भा०ज०पा० को प्राप्त नहीं है। हम न उग्रवादियों का समर्थन करते हैं, हम तो जो नरसंहार करने वाले लोग हैं, उस प्रवृत्ति को समाप्त करना चाहते हैं ... (व्यवधान ...) इसीलिए केन्द्र सरकार से, गृह मंत्री से आग्रह है कि आज आठ-दस जिले गया, नवादा, जहानाबाद, पटना भोजपुर, पलामू हजारीबाग, चितारा इन जिलों को आप अपने अंडर में ले लीजिए। ... (व्यवधान ...) यानी केन्द्र सरकार की पुलिस का स्वच्छ शासन हो तभी बिहार के गरीबों की जान बच सकती है और पुलिस के ऊपर जो खर्च करने के लिए पैसा दिया जाता है न वह पुलिस को प्रोपर पैसा दिया जाता है न आर्म्स दी जाती हैं, उसकी व्यवस्था कर दीजिए। डिस्क्रिमिनेश बिटविन हिन्दू-मुस्लिम में नहीं होना चाहिए। जान सबकी बराबर

है, एमाउन्ट सबको बराबर मिलना चाहिए 1 या दो लाख किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत नहीं हो सकती। अगर दो लाख रुपये देकर* आगे इसी प्रकार की हत्या करना चाहते हैं तो कोई दस लाख रुपये देकर हत्या करायेगा।

इसलिए पैसा देने से हत्याएं रुक नहीं जायेंगी। लेकिन हत्याओं में मारे गये लोगों के परिवारों की सुरक्षा के लिए लाख, दो लाख देना होगा। उनकी परमानेन्ट व्यवस्था कीजिए। उनकी व्यवस्था सिर्फ लाख-दो लाख देने से नहीं होगी। उनकी परमानेंट व्यवस्था की जाए। उनको नौकरी दी जाए, उनको जमीन दी जाए और उनको सुरक्षा दी जाए। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो वहां पर उग्रवाद पनप रहा है उसको रोकिए, नहीं तो कल हो सकता है कि हमें यहां पर गया के बारे में चर्चा करनी पड़े। इसलिए लगातार हो रही ऐसी हत्याओं को रोकने के लिए आप कदम उठायें। ... (व्यवधान ...)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठिए, कोई खतरा नहीं है। ... (व्यवधान ...) माननीय गृह मंत्री जी आप स्पष्टीकरणों का जवाब देंगे। ... (व्यवधान ...)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): Madam, if I understood you correctly, you had asked the hon. Members to seek clarifications by way of putting some questions arising out of the statement. I have been a Member of the other House for so many years. I am a bit taken a back because in our House we don't allow this kind of a debate on statements. Here we have had a mini debate but very useful, I must say. The hon. Members have not only put questions, they have also expressed their views and they have made various suggestions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Home Minister, while putting questions, hon. Members seek certain clarifications. In our House there is a provision for seeking clarifications. So while seeking clarifications they have tried to explain the whole situation.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I am not complaining about it at all. After all, this is a very painful and very shocking incident out of which the statement has come. I quite agree with those Members who apprehend that unfortunately this may not be the last occasion on which this type of an incident is brought to the notice of the country and has to be discussed in this House. There are some questions, pointed questions, which have been put. I will just try to reply to a few of them before making some general remarks.

Some hon. Members wanted to know whether this was an act of retaliation. I cannot give full details about it until we have obtained further detailed report from Bihar. After my visit there—I am going to visit that village and make an on-the-spot inquiry—I hope to be in a position after a few days, if you so permit, to make a fuller statement in this House which may cover many of these detailed points which the hon. Members want to know.

SHRI GOVINDRAM MIRI (Madhya Pradesh): May I know the date of your visit?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Please don't interrupt. Kindly sit down.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I will tell you. Many hon. Members have said here correctly that this is something which is a part of the process which has been going on for many years in about half a dozen districts of Bihar. Some people have said that 1000 killings have taken place. It is a fact there is some sort of a—what shall I call it—civil war, caste war going on in Bihar, not throughout Bihar but in some districts. It is a shocking thing to realise that the number of killings that have taken place, the number of deaths which have taken place may really exceed the casualties which people have suffered in Kashmir or the Punjab. It is quite correct to say that loyalty to a particular caste or a particular community has become predominant and it is not, I am afraid, in Bihar alone...*(Interruptions)*...

श्री एस०एस० अहलूवालिया: मैडम, यह तो प्राब्लम है, यह माइक सिस्टम तो बिल्कुल काम नहीं कर

*Expunged as ordered by the Chair.

रहा है। टोटली माइक सिस्टम इज़ डिस्टर्ब्ड।.....(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): यह माइक के सिस्टम को बंद ही कर दीजिए। .....(व्यवधान)

SHRI V. NARAYANASAMY: We are not able to listen .ÄÄ.*(Interruptions)*....

श्री एस०एस० अहलुवालिया: यह इलैक्ट्रानिक सिस्टम की गड़बड़ी हो रही है। ....(व्यवधान)

SHRI INDRAJIT GUPTA: I believe that this has to be looked at as a national problem....*(Interruptions)*.... Can I be allowed to speak without the mike? I think they will be able to hear me.....*(Interruptions)*.....

As I was saying earlier, this is a problem which will not be solved if treated on a local plane. I will just remind you that, not so very long ago, a former Home Secretary of the Union Government, Mr. N. N. Vohra had produced a report, in the course of which he came to the devastating conclusion that a nexus was operating in this country, a nexus of criminals who were tied up with some sections of the business community who were in turn tied up with some sections of the bureaucrats and some such other people. They have formed a nexus and that nexus is now, according to Mr. Vohra's report, virtually running a parallel Government in this country. This is the conclusion of a former Union Home Secretary which has come in the form of a published report. This is not something confined to Bihar or confined to any one State. This is something which is quite overpowering in its dimensions and the whole of our society, I feel, is now in the grip of this kind of a nexus in greater or lesser degree in different parts of the country. About corruption, of course, everybody knows. We cannot mention it here. But it is being talked about that various agencies and organs of the Government have become thoroughly infected as a result of this corruption and they are going by their loyalty to a particular community, particular caste, maybe, in some cases to particular parties as well. I am not in a position just now ...*(Interruptions)*.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Madam, we are on a specific point. We are not discussing the scenario of the entire country, of what is happening in Kerala or Calcutta or what has happened in the Bombay blast. I am concerned about the Bihar massacre and the statement is also given on that. We have put specific questions to the Minister and we expect specific answers.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Unfortunately, many of the questions were not specific at all. They were just as vague, as rambling.....*(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: I have put certain questions. Were they not specific?

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Minister, will you yield for a minute? You may recall that when I sought clarifications, the hon. Vice-Chairman observed that I should put specific questions on the subject. And I did not deviate from the subject. So, at least reply to those questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): He is coming to the point. You don't worry.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Have some patience and listen....*(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: We will definitely hear you. But we cannot have a half-an-hour discussion on it....*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Narayanasamy, kindly take your seat.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I begin with one such specific question.

This act of retaliation-बदला लेने का सवाल था। किसी ने पूछा था। आप ने?

डा० जगन्नाथ मिश्र: यस।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: तो फिर, उस का जवाब मैं दे रहा हूं।

What I am trying to say is that this particular incident may have been an act of retaliation. But that is not going to solve the problem because tomorrow there may be an act of counter-retaliation as has been happening in this area for a long time. Another question was put whether it is a fact that the people of this village had made repeated requests to the police for proper security measures and that their requests were ignored. Well, I am not in a position to tell you how many requests were exactly made and how many times they were made. But I do know, as somebody here has mentioned, that there were four police camps posted around this village. But when the time came and the killing took place, the massacre was going on, these four police camps appeared to be completely paralysed and impotent, and the personnel manning these camps, we are told now, did absolutely nothing to check the killers or to apprehend them. If this is true, it is certainly a matter of deep shame. Regarding fire arms, of course, we know that AK-47 and AK-56 are very sophisticated weapons. The only trouble is that nowadays they have become very easily procurable. You can buy them in the market...*(Interruptions)*

SHRI S.S. AHLUWALIA: This is so after the Purulia incident.

SHRI INDRAJIT GUPTA: It is not after the Purulia incident, my friend, but after the war in Afghanistan and so on. Throughout Pakistan, Punjab and everywhere, these arms have become plentifully available in the market. And they are being bouht by various people who are interested. Therefore, I will not be surprised if this type of Ranbir Sena or some of the other people also have got the AK-47. But our police have not got it. That is the only sure thing. Our police force is not equipped with the AK-47 and all that. So, they are at a disadvantage always in that sense. The next question was: Why should Naim be paid compensation? That has been explained here by some Members of the Communist Party who took the trouble of going to the spot before anybody else. They said that this Naim is a person who was accused of being responsible for the killing earlier of two supporters of Ranbir Sena. In that sense, this may have been a retaliation. But within his own family within his own house, five or six of his family members were butchered. Therefore, the Chief Minister has apparently thought it fit that he should be given Rs. 2 lakhs as compared with Rs. 1 lakh given to other victims.

SHRI K.R. MALKANI: In that case, it should have been Rs. 5 lakhs. If five lives were lost, then the amount should have been Rs., 5 lakhs.

SHRI INDRAJIT GUPTA: It is a mathematical argument. Of course, it should be looked into.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: We were the only people ...*(Interruptions)*...

SHRI INDRAJIT GUPTA: Somebody has asked ....*(Interruptions)*....

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Minister, you please control your comrade. He is passing remarks on other Members belonging to other parties. Members of every political party had visited the place.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I have never said that.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Mr. Gurudas, don't behave like that.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Mr. Ahluwalia, I have never said that. Madam Vice-Chairman, I take very strong objection to Mr. Ahluwalia's charge.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती कमला सिन्हा): बैठकर कोई कुछ बात करे, उसका जवाब ही नहीं देना चाहिए। गुरुदास दासगुप्त जी, उन्होंने बैठकर बात की है आपस में, आप जवाब क्यों दे रहे हैं। आप कृपा करके बैठ जाइए। ....**(व्यवधान)**....

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Should I not, as a Member of this House, take this seriously; I had said when the hon. Member on the other side was talking about the compensation ....(*Interruptions*)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Gupta, how could you speak like that? Did you take my permission? I did not permit you to say anything. So, kindly sit down. Nothing will go on record.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is his habit to interrupt every sentence of others.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI KAMLA SINHA): Mr. Minister, please continue.

SHRI INDRAJIT GUPTA: I have been informed by the Bihar State authorities that enhanced compensation is being considered for other victims of the incident also. Maybe, some of them would get more money than what was announced.

I would now genrally deal with the Senas. I don't know how many Senas are there. If you like, I will find out when I go there and inform the House later on. There are a number of Senas. We have been hearing about them for quite some time. This particular Ranbir Sena was a banned organisation. As you know, it was banned about a year ago. This kind of a ban in that kind of an area apparently does not have much effect in curbing their activities unless the police and the law and order enforcement machinery is something very different from what it is in the country; I am sorry to say this. I think one has to admit that the State Governments have to be given the prime responsibility of handling these Senas and their activities in such a vast country as ours.

Some general questions, such as the steps that are going to be taken to protect the weaker sections and all that, have been asked. This is a matter which will have to be worked out in much more detail. Then, in consultation and in co-operation with the various State Governments, including the State Government of Bihar with whom we proposed to interaet, ways and means have got to be worked out to see that the security apparatus is strengthened. We have got our own security apparatus. The State have got their own agencies. The Centre has got its own agencies, particularly the intelligence agency, which should be in a position to at least forewarn the people of this kind of attacks being planned or likely to take place. There is no previous warning received any time. Always an incident takes place as it appears to be a sudden one, someting which has come about suddenly. That means, there is planning and preparation behind these attacks which is not being identified and located in time by the intelligence agencies whose job it is to find out.

6.00 P.M. All these matters will have to be gone into. It is difficult for the Centre to do anything except to give directions and guidance to the State administrations so that they can bring about various improvements in the Police administration, in the recruitment of police, in the training of police and, as I have said, in their mindset; the mindset of the police is a very important matter. It is very difficult, of course, to change but the mindset could develop. I quite agree with the hon. member who said that the police and other similar type of forces are very often themselves divided in their caste and community loyalties. And, there are many times in our Parliament when we have been discussing the need of equipping and producing such forces, law enforcement forces, which will be composed of people of different communities, mixed forces which will not act in a prejudiced manner for or against any particular caste or community. We have not succeeded so far. But this line, I believe, has got to be pursued.

We will have to share our Intelligence information, the Centre and the States together and the States between

themselves also have to consider as to how they can share their intelligence information. There are several States in this country where the borders of those States are being infiltrated and are being transgressed and used by groups who believe in violence and believe in using arms for settling their various quarrels and scores, who are crossing over from one State to another. Without inter-state coordination and cooperation in Intelligence activity, all these things cannot be ever checked or halted.

Modernisation of police force is required certainly with regard to weapons, with regard to other equipment, with regard to vehicles, transport and all that and most of the States now-a-days, I may say, are pressurising the Centre to give them more and more financial assistance in order to modernise forces, obviously in Bihar also. These police forces are ill-equipped, probably not sufficiently trained also. But the same demand is coming from many States including Assam, Tripura, Andhra Pradesh and so many States which are widely separated from each other, which are confronted with similar type of problems.

Then, when a particular incident takes place, some stringent penal measures have to be taken against the people responsible. At one time, we had, I think, laid down some kind of a norm that whenever any disturbance or violent incident of this type resulting in deaths and killings takes place in a particular area or State, then the District Magistrate and the S.P. should be first of all taken to task and held responsible for what has happened. I do not know what has happened to that norm or that principle. I am not aware whether anybody observes it or sticks to it. I am new to this job but I will certainly try to find out.

There is an Indian Police Commission report which is lying there, gathering dust on the shelf, some bulky volumes, which contain, as far as I know some very, very valuable recommendations as to how this whole Police Force is to be reorganised and made much more effective. Within a few days, I am told, the Annual Conference of the Directors-General of Police is going to be held in Delhi—it is held every year—and, I think, that is an occasion when, utilising the lessons that we have to learn from this type of incident which has taken place in Bhojpur, the Directors-General of Police may also consider and discuss in some detail in their Conference as to what urgent measures are required to be taken in order to curb this kind of a thing.

But I agree that it is basically not a law and order problem. It is basically a political and social problem, Madam. It is a question of landlessness in a place like Bihar. Millions of our landless people are there, not today but for years together. together. Land is the basic use on the one hand, there are huge numbers of landless agricultural labour and other landless people and on the other hand, there are big land-owners who are, I think, behaving in much the same way as they used to do in the British days. I don't find any change. In the days of the British also big rajas, maharajas and feudal lords used to go around killing poor landless people and their tenants whenever they wanted to, there was no protection for them at all.

Now, questions are being asked here, quite rightly, what steps you propose to take to protect the poorer sections. Many steps can be suggested, but much more than their suggesting steps in the question of implementation. Very good suggestions and steps are suggested, but when it comes to implementation it becomes rather a difficult problem in this country and in our society. There are so many forces at work, so many pulls and pressures. As Mr. Vora has said, there is a nexus working which prevents you from carrying out and implementing those salutary suggestions which are in a sense very good. So, all I can say at this stage is that I hope to visit Bihar in a day or

o. I would, of course, not only visit it particular village and talk to the ople there, but also I propose to have me discussions with the Chief Minister id other authorities of the Bihar State ho are concerned and to hear from iem also what they are thinking and ow they propose to tackle this problem which is spreading in Bihar all the time and which will spread to other States also. It has different forms. Of course, different forms of violence are perpetrated. It is not always the same kind of thing. It is not always retaliation, sometimes something else, extortion, forcible extortion of money or something or other. These things are going on. This cult is spreading; It is spreading. It is not under control and we have proved ourselves really quite powerless to check it up till now. Therefore, I would only request the House to have patience for a few more days till we are able to get a fuller picture, a more detailed picture of the Bhojpur happenings the role of the State Government, the role of the State police authorities, whether the Centre can do something more effective sitting here in Delhi, or weather their responsibilities must only be limited to advising the State Government on what to do, and to giving them guidelines and directions, and so on. It is very difficult to do anything diectly so long as law and order is a State subject. Madam, primarily, it is the State Governments which have to deal with the problem. I don't agree with the friends here who have said that what is happening in Bihar is a clear evidence of the total breakdown of the law and order machinery and therefore, Article 356 should be applied. We have received no such message or anything from the Governor. Of course, what is happening is quite deplorable. There is no doubt about it.

SHRI V. NARAYANASAMY: What does the last sentence of your statement say? You have said there that the administration is ineffective and inefficient.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Ineffective and inefficiency is not enough ground in our Constitution to impose President's rule.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Have you asked for any report from the Governor?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Why should we ask for a report.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Are you going to declare these districts as distrubed areas?

SHRI INDRAJIT GUPTA: There is no intention, at present.

We have declare many places in this country, in Assam, in Manipur, in Nagaland and in so many places, as disturbed areas and applied special laws to them including Special Army Act and all that, and there is no improvement. Things are going on just as they always work. So, we will have to give a much deeper thought to this. It is not a superficial matter. I hope, all of us here rising above party loyalties will treat this matter as a serious national problem. Let us give it a much deeper thought. We can arrange some further detailed discussions or seminars or whatever you like, but we must not think that only by strengthening the security forces we are going to solve this problem. It has never been solved like that. Even those people who believe in the cult of gun all these years, I think, in Kashmir and other places, are beginning to give up that theory. It does not work. It does not work, unless you have political and social measures to deal with the real grievances of the people and to help them to think that they can lead more satisfied life. You cannot get over this. There are millions of frustrated young unemployed people in this country who do not have any hope for themselves and who take to this kind of path also because they don't see any way-out. Unless we take social, political and economic measures of development and so on, we will not be able to cure this thing. The abject poverty in the villages of Bihar, I think, is known to Mr. Ahluwalia. It should be known to him; he comes from Bihar. I do not know whether he comes from this area. (*Interruptions*)

SHRI S.S. AHLUWALIA: I come from the most notorious area—Begusarai. (*Interruptions*)

SHRI INDRAJIT GUPTA: I think, for the time being, I really cannot throw any more light on the happenings in Bhojpur. After I come back from there, I hope, I would be able to bring a lot of information and facts, perhaps. I hope the House will have patience till that time to listen to my statement and on that basis we will make some very meaningful suggestions and proposals which can be implemented so as to improve the e system.

Thank you.

THE VICE-CHAIRM (SHRIMATI KAMLA SINHA): Th you. The House stands adjourned till o'clock tomorrow, the 16th July, 199

The House then adjourned at twelve minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 16th July, 1996.